



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, सोमवार, 03 मार्च, 2025 ई०

(फाल्गुन 12, 1946 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-4099/दस-लाइसेंस-59/देशी शराब/2025-2026

प्रयागराज, दिनांक 03 मार्च, 2025 ई०

अधिसूचना

सा०प०नि०-१७

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24 और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, आबकारी आयुक्त की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या-27091/दस-लाइसेंस-59/2002-2003, दिनांक 14 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश, आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)

(अठारहवां संशोधन) नियमावली, 2025

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (अठारहवां संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गज़ट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-नियम-2 का संशोधन-उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम-2 के उपनियम (1) (क) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (झ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
<p>(झ) "धरोहर धनराशि" का तत्पर्य लाइसेंस प्रदान करने के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जाने वाली बेसिक लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबंधों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी;</p> <p>(ड)" अनुक्रम" का तात्पर्य ई/लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंस धारी के चयन के लिये कथित आधार दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है;</p>	<p>(झ)- निकाल दिया गया।</p> <p>(ड)" अधिक्रम" का तात्पर्य ई-लाटरी में लाइसेंसधारी के चयन के लिये कम्प्यूटर आधारित यादचिकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से दुकान आवंटन के आधार हेतु तात्परित दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस के अवरोही क्रम से है।</p>

3-नियम-5 का संशोधन- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
<p>5- लाइसेंस की अवधि-</p> <p>लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी, किन्तु लाइसेंसधारी की इच्छानुसार अनुज्ञापन अगले आबकारी वर्ष के लिये राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित उपभोग के मानदण्ड के अनुसार नवीनीकृत अथवा विस्तारित किया जा सकेगा।</p>	<p>5- लाइसेंस की अवधि-</p> <p>लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग, जिसके लिये लाइसेंस प्रदान किया गया है, होगी, किन्तु अगले आबकारी वर्ष हेतु लाइसेंसधारी का चयन इस नियमावली के नियम-10 के अनुसार किया जायेगा।</p>

4-नियम-10 का संशोधन- उक्त नियमावली, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
<p>10-लाइसेंसधारी का चयन</p> <p>(क) (एक) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन दुकान के लाइसेंस का ऑनलाइन नवीकरण किया जा सकेगा।</p> <p>(दो) नवीकरण न होने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का चयन, आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर की प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी, आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और पत्र एवं अपात्र आवेदनों की सूची, अपात्रता के कारणों को उल्लिखित करते हुए तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।</p> <p>परन्तु यह कि अगले वर्ष दुकान के नवीकरण हेतु धनराशि को जमा करने के पश्चात यदि किसी लाइसेंस धारी की मृत्यु हो जाती है और उसके किसी विधिक वारिस अथवा नामनिर्देशिती द्वारा लाइसेंस के संचालन हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाता है अथवा किसी वारिस/नामनिर्देशिती को इस हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है तब नवीकरण हेतु जमा धनराशि(प्रासेसिंग फीस को छोड़कर) विधिक वारिस को वापस कर दिया जायेगा।</p>	<p>10-लाइसेंसधारी का चयन</p> <p>(1) (क) किसी दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन की ई-लाटरी, ई-नवीकरण तथा ई-टेण्डर की तीन प्रक्रियाओं में से किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा उस विशिष्ट वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट हो।</p> <p>(ख) राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष हेतु नवीकरण विनिर्दिष्ट न किये जाने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का दुकानवार चयन, आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ई-लाटरी अथवा/एवं ई-टेण्डर की प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। यदि राज्य सरकार द्वारा ई-नवीकरण विनिर्दिष्ट किया जाता है किन्तु लाइसेंसधारी द्वारा नवीकरण का अनुरोध नहीं किया जाता है अथवा लाइसेंसधारी नवीकरण हेतु पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी पूर्वोलिखित ई-लाटरी अथवा/एवं ई-टेण्डर प्रक्रिया अपनायी जायेगी। जिला आबकारी अधिकारी, आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और समस्त ग्राह्य एवं अग्राह्य आवेदनों की सूची, अग्राह्यता के कारणों को वर्णित करते हुए तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु इस नियमावली के नियम-9 में यथाउलिखित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।</p> <p>(ग) यदि दुकान का नवीकरण कर दिया गया हो, की स्थिति में और नवीकरण शुल्क जमा करने के पश्चात यदि किसी लाइसेंस धारी की मृत्यु हो जाती है और उसके किसी विधिक वारिस अथवा नामनिर्देशिती द्वारा उक्त लाइसेंस के संचालन हेतु आवेदन नहीं दिया जाता है अथवा किसी वारिस/नामनिर्देशिती को इस हेतु पात्र नहीं पाया जाता है तो नवीकरण हेतु जमा धनराशि, प्रासेसिंग फीस को छोड़कर विधिक वारिस के पक्ष में प्रतिदाय कर दी जायेगी।</p>

स्तम्भ-1 वियमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
<p>(ख) उक्त समिति आवंटन हेतु अर्ह एवं अनर्ह आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में अर्ह आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चलित याद्विषयक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। याद्विषयकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मंदिरा, माडल शाप, विदेशी मंदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन की स्थिति में उसी पूर्वान्त अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष सम्पूर्ण राज्य में सभी श्रेणी की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मंदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी।</p> <p>परन्तु यह कि पूर्वान्त निर्बंधन सीमा लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों की मृत्यु की स्थिति में नियम-8(क) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार मृत लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के विधिक वारिस/परिवार के सदस्य/निकट संबंधी के पक्ष में लाइसेंस नवीकरण/नामांतरण से संबंधित मामलों में लागू नहीं होगा।</p> <p>परन्तु यह और कि किसी आवेदक के पक्ष में संपूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों के नवीकरण होने की स्थिति में वह ई-लॉटरी के माध्यम से अग्रतर दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा।</p>	<p>(2) ई-लॉटरी की स्थिति में पात्र आवेदकों में से दुकानवार लाइसेंसधारी का चयन नियम 2(1)(झ) में यथा परिभाषित प्रत्येक श्रेणी में अधिक्रम के अनुसार देशी शराब की दुकान, माडल शाप, कम्पोजिट शाप और भांग की दुकान श्रेणियों के अनुक्रम कम्प्यूटर आधारित याद्विषयक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा।</p>
<p>(ग) यदि चयनित आवेदक बेसिक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताए पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।</p>	<p>(3) यदि लाइसेंसधारी का चयन ई-टेण्डर के माध्यम से किया जाता है तो टेण्डर/आफर आमंत्रित करने की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी।</p>

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान उपनियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
<p>(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल उपाय करेगा।</p>	<p>(4) सम्पूर्ण राज्य में किसी भी व्यक्ति के सभी श्रेणी की देशी शराब की दुकान, माडल शाप, कम्पोजिट शाप एवं भांग दुकानों सहित दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी :</p> <p>परन्तु यह कि नवीनीकरण/नामांतरण के मामलों में पूर्वोक्त निर्बंधन विधिक वारिस/परिवार के सदस्य/निकट संबंधी के पक्ष में लागू नहीं होगा :</p> <p>परन्तु यह और कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों के नवीनीकरण होने अथवा दो या दो से अधिक दुकानें पूर्व से व्यवस्थित होने की स्थिति में, वह ई-लाटरी/ई-टेण्डर के माध्यम से अतिरिक्त दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा।</p> <p>(5) ई-लाटरी अथवा ई-नवीनीकरण अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति को बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समयसारणी एवं रीति के अनुसार जमा करना, तथा समस्त अन्य विनिर्दिष्ट औपचारिकताएँ पूरी करना तथा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर उपर्युक्त दुकान परिसर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। यदि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किया जाता है तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन/लाइसेंस को निरस्त कर देगा और दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक कदम उठायेगा।</p> <p>(6) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए यथा स्थिति ई-लाटरी अथवा ई-नवीनीकरण अथवा ई-टेण्डर प्रक्रिया में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल कदम उठायेगा।</p>

(डा. आदर्श सिंह)

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 4099/X-License-59/Country Liquor /2025-26

*Prayagraj, Dated : March 03, 2025***NOTIFICATION**

In exercise of the powers under sections 24 and 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Country Liquor) Rules, 2002 published vide Excise Commissioner notification no. 27091/X-Licenes-59/2002-2003, dated March 14, 2002 and as amended time to time.

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENSES FOR RETAIL SALE OF COUNTRY LIQUOR) (EIGHTEENTH AMENDMENT) Rules, 2025

1-Short title and commencement-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Country Liquor) (Eighteenth Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2-Amendment of rule-2—In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Country Liquor) Rules, 2002, for sub rule-(1)(i) and sub rule-(1)(m) of rule-2 setout in Column-1 below, the sub rules as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column I (<i>Existing sub rules</i>)	Column II (<i>Sub rules as hereby substituted</i>)
2(1)(i) "Earnest Money" means the amount equal to 1/10 of the amount of basic license fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of license and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these rules;	2(1)(i) Deleted.
2(1)(m) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e/lottery;	2(1)(m)"Hierarchy" means the descending order of the basic license fee of shops purported to be the basis for shop allotment through the process of computer based randomization in e-lottery for selection of licensee;

3. Amendment of rule-5—In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Country Liquor) Rules, 2002, for rule 5 setout in Column-1 below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column I (<i>Existing sub rules</i>)	Column II (<i>Sub rules as hereby substituted</i>)
5-Period of License The period of licence shall be for an excise year or part thereof for which the licence has been granted, but the licence may be renewed or extended for the next excise year according to the parameter of consumption as fixed by the State Government.	5- Period of License The period of licence shall be for an excise year or part thereof for which the licence has been granted, but the selection of licensee for the next excise year shall be in accordance with the rule-10 of these rules.

4. Amendment of rule-10—In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Retail Sale of Country Liquor) Rules, 2002, for rule 10 setout in Column-1 below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column I <i>(Existing sub rules)</i>	Column II <i>(Sub rules as hereby substituted)</i>
<p>10- Selection of licensee-</p> <p>(a) (i) License of shop may be renewable online under the terms and conditions specified by the State Government.</p> <p>(ii) In case of non-renewal, licensees shall be selected shop wise through the process of e-lottery or e-tender, as specified by the State Government, through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender.</p> <p>Provided that if a licensee dies after depositing the amount for renewal of shop for the next year and no application is made by any of his legal heirs or nominees for operation of license or no heir/nominee is found suitable for this purpose, then the amount deposited for renewal (except processing fee) will be returned to the legal heir.</p>	<p>10- Selection of licensee-</p> <p>(a) (i) The licensee for a shop shall be selected from amongst the three processes of E-Lottery, E- Renewal and E-Tender which ever is/are prescribed by the State Government for that particular year.</p> <p>(ii) In case E-renewal is not prescribed by the State Government for a particular year, the shop wise selection of licensee shall be made through the process prescribed by the State Government through E-lottery or/and E-tender by inviting online applications. If E-renewal is prescribed by the State Government but renewal is not requested by the licensee or licensee has been found ineligible for renewal, then in such case also the aforementioned process of E-lottery or/and E-tender will be adopted. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare a list of all admissible and in admissible applications, describing the reasons of in admissibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing as mentioned in rule-9 of these rules for e-lottery and e-tender.</p> <p>(iii) If the shop has been renewed and if the licensee dies after depositing the renewal fee and none of his legal heirs or nominees apply for the operation of the said license or if the legal heir/nominee are not found eligible for the purpose, the amount deposited for renewal except processing fee, shall be refunded in favor of the legal heir.</p>

Column I <i>(Existing sub rules)</i>	Column II <i>(Sub rules as hereby substituted)</i>
<p>(b) The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of lottery the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the order of country liquor, model shops, foreign liquor and beer shops as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two shops including all categories of country liquor, model shop, foreign liquor and beer shall be allotted in favour of an applicant in the entire State.</p> <p>Provided that aforesaid restriction limit shall not be applicable to matter related to renewal of licenses and mutation of licence in favor of legal heir/family member/close relative of deceased licensee/licensees in the event of death of licensee/licencees as per the procedure mentioned in rule-8(a).</p> <p>Provided further that in case of renewal of two or more shops in favour of any applicant in the entire state, he will be ineligible for selection of further shops through e- lottery.</p>	<p>(b) In case of e-lottery the shop wise licensee shall be selected from amongst the eligible applicants through computer based randomization process in sequence of country liquor shops, model shops, composite shops and bhang shops categories as per the hierarchy in each category as has been defined in rule-2(1)(m).</p>
<p>(c) In case the selected applicants does not deposit the required basic licence fee or security amount and does not fulfill the prescribed formalities or is unable to arrange suitable premises for the shop within the stipulated period, the Licensing Authority shall cancel the allotment and take steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.</p>	<p>(c) In case the selection of licensee is done through E-Tender, the process of inviting tender/offer shall be prescribed by the State Government.</p>
<p>(d) In case there is no application for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the State Government.</p>	<p>(d) Not more than two shops including all categories of country liquor shops, model shops, composite shops and bhang shops shall be allotted to any person in the entire State.</p> <p>Provided that in case of renewal aforesaid restriction shall not apply in matters of renewal/ mutation in favour of legal heir/family member/close relative.</p>

Column I <i>(Existing sub rules)</i>	Column II <i>(Sub rules as hereby substituted)</i>
	Provided further that in case two or more shops are renewed or already settled in the State in favour of an applicant, he/she shall not be eligible for further allotment of shops through E-Lottery/E-Tender.
	(e) It shall be mandatory for the person selected as licensee through E-Lottery or E-Renewal or E-Tender to deposit basic license fee and security in the time schedule and in the manner prescribed by the State Government and, complete all other prescribed formalities and make arrangement for appropriate shop premises within the prescribed time period . In case the person selected as licensee does not comply with the above, the Licensing Authority shall cancel the allotment/license and shall take necessary steps for the resettlement of the shop as prescribed by the State Government .
	(f) In case there is no application for a particular shop in E-Lottery or E-renewal or E-tender process as the case may be, or no candidate is found suitable for the shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the State Government.

Dr. Adarsh Singh,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.